

संख्या
तहसील
म की
जा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 11/19

GCMS NO 2019/00017

गोपाल पुत्र मूलचंद जाति छीपी निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
.....अपीलांत

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

..... रैस्पोंडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.17

मु0नं0 156/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मो0इस्लाम खान
अभिभाषक रैस्पोंड पैंरोकार सरकार

दिनांक 30.09.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रैस्पोंड/ वादी तहसीलदार वजीरपुर ने वाद पत्र धारा 177 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी/अपीलांत द्वारा खसरा नं0 5611/3464 रकबा 0.0331 है0 ग्राम वजीरपुर में भूमि रकबा 224 वर्गमीटर में विना भूमि की किस्म परिवर्तन करायें मोबाईल टावर लगा दिया। खातेदार द्वारा खातेदारी शर्तों की अवहेलना की गई है। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की गई है। इस प्रकार अपीलांत को बेदखल कर भूमि को सिवायचक दर्ज की जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रैस्पोंड का वाद स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया रैस्पोंड को नोटिस जारी किये, तहत रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगणों की सुनी गई ।

अपीलांत के योग्य अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस अपील में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री का सही विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु कय की है, जिसकी रजिस्ट्री अपीलाधी द्वारा दिनांक 13.2.08 को तहसील वजीरपुर में कराई गई है। जहाँ पहले से ही भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु कय की गई हो तो खातेदारी शर्तों की अवहेलना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। भूमि खातेदारी होने पर उसका वाणिज्यिक




राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रयोजन किये जाने पर खातेदारी शर्तों की अवहेलना माना जावेगा। उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो आर्डर प्रारंभ से ही शून्य है उसके लिए कोई मियाद लागू नहीं होती है। उसे कभी भी चलेन्ज किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.6.17 का है लेकिन उक्त ओदश पर अपीलार्थी से यह कहकर हस्ताक्षर कराये गये थे कि उक्त पत्रावली को निरस्त किया जा रहा है। लेकिन बाद में राजस्व अभियान में उस पर गलत रूप से धारा 177 आर टी एक्ट के दावे को डिकी कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह सशर्त आदेश पारित किया गया है जिसमें एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। जो न्यायिक सिद्धान्त की परिभाषा में नहीं आता है। इस प्रकार अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त फरमाई जावे।

रेस्पों के विद्वान अभिभाषक परोकार सरकार ने अपील बहस में बताया कि अपीलांत द्वारा खसरा नं० 5611/3464 रकबा 0.0331 है० ग्राम वजीरपुर में भूमि रकबा 224 वर्गमीटर में बिना भूमि की किस्म परिवर्तन करायें मोबाईल टावर लगा दिया। खातेदार द्वारा खातेदारी शर्तों की अवहेलना की गई है। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की गई है। इस कारण ही तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलांत के विरुद्ध धारा 177 आर टी एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा दिनांक 30.6.17 को विवादित भूमि को कनवर्जन का आवेदन संबंधित कार्यालय में पेश करने का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार अपीलांत की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन से यह तथ्य सामने आये कि खसरा नं० 5611/3464 रकबा 0.0331 है० ग्राम वजीरपुर में भूमि रकबा 224 वर्गमीटर में बिना भूमि की किस्म परिवर्तन करायें मोबाईल टावर लगा दिया जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी नियमों की अवहेलना मानी जाने के फलस्वरूप सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं परन्तु अपीलांत अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि विवादित आराजीयात को अपीलांत द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय की गई है इस कारण खातेदारी के प्रावधानों की अवहेलना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलांत द्वारा दिनांक 13.2.08 को तहसील कार्यालय वजीरपुर में उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने का कथन किया गया है। अपीलांत का कथन रहा कि भूमि पर लगाये गये टावर की भूमि को अपीलांत रूपान्तरित कराने हेतु प्रयासरत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह सशर्त आदेश पारित किया गया है जिसमें एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। जो न्यायिक परिपेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलांत के इस मत से मैं सहमत हूँ। अपीलांत की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी का निर्णय व डिकी दिनांक 30.6.17 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रकरण मे अपीलान्ट को सुनवाई एवं सबूत का पर्याप्त समय दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनःनिर्णय पारित करे।



निर्णय आज दिनांक 30.9.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/9/24
(लक्ष्मीकान्तबालोत) श्री
राजस्व अपीलान्ट प्राधिकारी